

5.24 hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(Substitution of article 6)

श्री बिलामक प्रसाद यादव (महरसा) - उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का धीरे-समोहन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

यह जो संविधान (समोहन) विधेयक मैं लाया हूँ, उसका उद्देश्य स्पष्ट है। इस विधेयक के उद्देश्यो धीरे-काणो के रूप में मैंने कहा है "वर्णाश्रम धीरे-द्विजाद पर आधारित भारतीय समाज के वर्तमान गठन से आत्मादी की बहुमध्यक तादाद नार्नामक धीरे-आगीरिक् तौर पर लुप्त बन गई है। इसके पलम्बरूप आत्मादी के सिर्फ 10 प्रतिशत मगदाय ने सरकारी, अर्द्धसरकारी धीरे-सरकारी मकाभा की 90 प्रतिशत जगहो पर एकाधिकार स्थापित कर लिया है। पचन प्रायं दिन कमजोर वर्गो पर हमला, कले-धाम धीरे-आगानी का घटना बढती जा रही है। इस विधेयक में उद्देश्य उपरान्त एकाधिकार का समाप्त करना धीरे-समाज तथा प्रजातन में ब्याप्त असंतुलन को दूर करना है।"

हमारा जो संविधान है, उसमें जो फुडामेटरा टाइटल है उनका आप देखें धीरे-आर्टिकल 16 (4) को आप पढ़ें तो उसमें यह स्पष्ट है—

"Nothing in this article shall prevent the State from making any provision for the reservation of appointments or posts in favour of any backward class of citizens which, in the opinion of the State, is not adequately represented in the services under the State"

यह प्रावधान संविधान में पहले से है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि संविधान को जानू हुए 30-31 साल हो गए। इस 30-31 साल में जो सरकारी नौकरियों हैं उनमें जो एक्सेलन्सी धीरे-सोसली बैकवर्ड मजारा है, उनको स्थिति धीरे-बिगडी है। उनका रेप्रेजन्टेशन संविसेज में इन्फ्लोकेट को कौन कहते, जैसा कि संविधान में लिखा हुआ है कि इन्फ्लोकेट रेप्रेजन्टेशन है तो स्टेट को जानू बना कर उनको उनको आत्मादी के अनुसार सरकारी नौकरियों में बरह देना चाहिए, यह प्रावधान खुले हुए भी नत तीस सालों में स्थिति यह हो गई है कि इन्फ्लोकेसी का कौन पूछे, इनका रेप्रेजन्टेशन बिल्कुल नग्न हो गया है, कोई रेप्रेजन्टेशन ही नहीं है। अर्थोकी धीरे-कृत में बिलना बा उससे भी बट गया है। इसका कारण है कि आत्मादी के बाव एक सिद्धान्त थाया नया "इक्विटी का

अपार्थिन्टी" का, "समान अवसर का सिद्धान्त" थलाया गया कि हर एक नार्गरिक को हर अपार्थिन्टी समान रूप से मिलेगी धीरे-किसी के साथ जाति वरीरुह का भेदभाव नहीं किया जायगा। यह एक सिद्धान्त गाया गया। मैं आपके जरिए कहना चाहता हूँ कि आजाद हिन्दुस्तान में इससे ज्यादा धोखाधडी का सिद्धान्त कोई दूसरा नहीं चलाया गया। फर्ज कीजिए कि आप एक साक्षिक का रैन करवाना चाहते हैं। जब रेत शुरू होता है तो कुछ लोगों का दोहन बते हैं धीरे-15 मिनट के बाद फिर एक जयें को कहते हैं कि दोहा धीरे-कहते हैं कि जो पम्ह मिनट पहले दोहा है उससे तुम बम्पीट करो, तो क्या यह बम्पी समव है कि वह उसको कम्पीट कर सके? यहाँ ता भारतीय समाज का बहु-सक्यक वर्ग तीन हजार नमं पीछे पड़ गया। कैसे बराबरी कर सकेंगा ?

अभी हिन्दुस्तान के समाज की क्या स्थिति है ? समाज का अधिकांश मनुष्य लुप्त बन गया है। वह किसी काम का नहीं रहा धीरे-उसका सरकारी नौकरियों में कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं है। ऐसा इसलिए हुआ कि हमारे यहाँ हजारों बच से यह सिद्धांत था, एक मनु भगवान की व्यवस्था थी वर्णाश्रम धम धीरे-द्विजाद की कि फला जाति धीरे-फला बग डी बिधा पड़ बनना है। मनुस्मृति का आपने देखा होगा, उसमें लिखा हुआ है कि जो मूढ़ है या जो बैय है, उसका बिधा पड़ने का अधिकार नहीं है। यहाँ तक लिखा हुआ है कि यदि मूढ़ के कान में वेद वाक्य बना जाय या जान की बात चली जाय तो उसके कान में गन्म सीसा घोल कर डाल दिया जाय। यह है मनुस्मृति की व्यवस्था धीरे-उसके अनुसार लगभग तीन चार हजार वर्ष तक इस देश का धामन चला। इसी का नतीजा हुआ कि 90 प्रतिशत या 80 प्रतिशत लाग साक्षरों धीरे-एक्सेलन्सी बैकवर्ड हा गए, उनको पड़ने की अपार्थिन्टी नहीं दी गई, उनको जान की कोई बात नहीं सुनने दी गई। इसी का नतीजा यह हुआ है कि अधिकांश आत्मादी सरकारी नौकरियों से, इज्जत की जगह से महकूम कर दी गई है धीरे-मुट्टी भर, वस प्रतिशत आत्मादी का हिस्सा जो द्विज है उसी का बर्षत्व हो गया, उसी की मोनोपली हो गई। सरकारी नौकरी में, इज्जत की जगहों में धीरे-समाज के हर क्षेत्र में अन्य लोगों को पीछे अकेल कर ने भगुवा बन गये। जो संविधान बनाने वाले थे—बाई अम्बेडकर साहब हो, डा० राजेन्द्र प्रसाद हो या दूसरे लोग हो—उन्होंने इस असंतुलन का मजमा धीरे-हसी-लिए उन्होंने संविधान में अनुच्छेद 16(4) का प्रावधान किया ताकि इस असंतुलन का समाप्त किया जाए। लेकिन देश आजाद होने के बाद तीस साल तक ब्रिसेज की हुकूमत चली फिर भी आज तक इस असंतुलन को खत्म करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई बल्कि इस अन्त्या धीरे-असंतुलन को बरकरार रखने के लिये "समान अवसर" के सिद्धान्त को गड़ लिया गया।

[श्री विनायक प्रसाद यादव]

जहां तक हरिजन भादिवासियों का सवाल है, प्रायः भी उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। उनके लिए 30-31 साल से रिजर्वेशन है लेकिन अभी तक वह पूरा नहीं हुआ है। केवल 3-4 प्रतिशत भाग ही नौकरियों में पा सके हैं। इस सबब में सविधान में अनुच्छेद 335 का प्रावधान है

"The claims of the members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes shall be taken into consideration, consistently with the maintenance of efficiency of administration, in the making of appointments to services and posts in connection with the affairs of the Union or of a State."

हरिजन भादिवासियों के लिए सविधान में प्रावधान है इसलिए कानून बनाया गया कि सरकारी नौकरियों में इनकी जगहें उनका मिलनी चाहिए लेकिन पिछड़ी जाति के जा नाग हैं उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। उनका नतीजा यह है कि सरकारी नौकरों में उनका रिप्रजेन्टेशन उनकी भाबादी के हिसाब से तो कहना ही क्या, एक प्रकार से उनका रिप्रजेंटेशन नगण्य है। विगत तीस सालों में हरिजन भादिवासी की नौकरियों में बहाली की गई है लेकिन जो मुलतमान समुदाय है उनकी हरिजनों से भी बुरी हालत बना दी गई है। यदि वही व्यवस्था चलती रही तो मैं समझता हूँ 5-10 साल के बाद इस देश में कोई भी मुलतमान दारोगा नहीं मिलेगा, कोई मुलतमान मजिस्ट्रेट नहीं मिलेगा—भाई ए एन श्री भाई पी एस की तो बात ही छाड़ दोजिए। इससे पहले मुलतमानों की हालत हरिजन, भादिवासी तथा पिछड़ी जाति के लोगों से भी बुरी हो जाएगी।

उपरोक्त स्थिति का तो ध्यान में रखकर मैंने मौजूदा सविधान/संशोधन) बिल प्रस्तुत किया है। चाहता हूँ कि मौजूदा अनुच्छेद (16) कब बयल कर, रिया जाए। इसके द्वारा अभी जो आधिकारिक नौकरियों में घसतुलन है, जो प्रत्यक्षता है और जो प्रत्यक्ष है वह समाप्त हो जाएगी तथा समूचे देश का विकास सम्भव होगा। जब तक प्रशासन में पूरे समाज का भादिधिषणन नहीं होगा देश भ्रष्ट नहीं होगा।

एक बात मैं और कहना चाहता हूँ। सविधान के अनुच्छेद (340) में है कि सोशरी, एजुकेशनली पिछड़ी हुई जातियों के लिए एक कमिशन बनाया जाएगा और उसकी रिपोर्टें भ्राने बाद उनक सरअय की व्यवस्था की जाएगी। आप जानते हैं कि 1953-54 में काका कानेलकर कमिशन गठित किया गया था जिसने रिपोर्टें भी दी लेकिन आज तक उस रिपोर्टें पर कोई कार्यवाही नहीं की गई, कोई विचार नहीं किया गया। अब एक कांटेबिली बिल से शुरू कर दी गई है कि पिछड़ी जाति का कास्टीरिया क्या हो

सकता है—भायिक कास्टीरिया होना या सामाजिक कास्टीरिया होना? जहां तक सविधान का सवाल है, उसमें स्पष्ट है कि जो सामाजिक रूप से, जाति के हिसाब से, शिक्षा के हिसाब से पिछड़े हुए हैं वही पिछड़ी जाति के समझे जायेंगे। लेकिन फिर भी एक कांटेबिली बिली कर दी गई। मैं समझता हूँ मेरे इस बिल पर विचार करने और पास करने के बाद जो एनामी है, जो प्रत्यक्ष फीजा हुआ है वह समाप्त किया जा सकेगा। अभी सैकड़ों में बस प्रतिशत की भाबादी वाले ममुदाय में 90 प्रतिशत जगहों पर रखल कर रखा है और जो 80 प्रतिशत भाबादी है, उसको 5 परसेन्ट, और यहां तक कि 3 परसेन्ट भी जगहें न दी जाए, तो यह समाज कल नहीं मकता है और यह देश टूट जाएगा यदि इन चीजों को खत्म नहीं किया जाएगा। इसीलिए इस उद्देश्य से यह मौजूदा सविधान (संशोधन) विधेयक, प्रायः के जरिये हम सदन के विचार के लिए मैंने प्रस्तुत किया है और मैं समझता हूँ कि इन पर सदन अच्छी तरह से विचार करेगा फिर इन का पान करेगा

इतना कह कर मैं बैठता हूँ।

श्री बीनेज बट्टाचार्य (बीरपुर) : बुनियादी बात क्या है? what do you want?

श्री विनायक प्रसाद यादव : मैंने तो बात यह है कि जो बैकवर्ड क्लासेज हैं, जो माजनी और एजुकेशनली बैकवर्ड डिफाइन्ड हैं प्रायः क सविधान में, उन का जैसा सविधान में बिना हुआ है, उस के अलावा सरकारी नौकरियों की जाए। यदि कोई स्टेट यह समझती है कि किसी ममुदाय का सरकारी नौकरियों में इनएडिक्ट रेप्रजेंटेशन है तो इस के लिए कानून बना कर उन की भाबादी के अनुसार उन्हे सरकारी नौकरियों में जगह दी जाए। यह सविधान में भी लिखा हुआ है लेकिन आज से 30-31 साल पहले सविधान में लिखे जाने पर भी इस बात को कार्यान्वित नहीं किया गया है। इसलिए हमारे इस विधेयक का उद्देश्य यही है कि पवित्र सविधान में जो भाजिक चीज लिखी हुई है उसको करने के लिए प्रथम सविधान में कोई आमी है, तो उस को पूरा करने की व्यवस्था की जाए और इस देश में जितने लोग हैं, उन को उन की भाबादी के अनुसार उन का उचित हिस्सा मिलना चाहिए सरकारी नौकरियों में। जैसे प्रायः के जमीन के बंटवारे की बात बहुत ज्यादा पसन्द होती है, उसी तरह से प्रायः को सहानुभूतिपूर्वक इस पर भी विचार करना चाहिए क्योंकि यदि कुछ लोगों को जमीन के जरिये से जीविका मिलती है तो उसी तरह से कुछ लोगों को सरकारी नौकरियों के जरिये से जीविका के साधन मिलने चाहिए। जैसे पेट भरने के लिए जमीन का बंटवारा प्रायः कर है, उसी तरह से इस देश में कुर्सी का बंटवारा जब तक भाबादी क अनुपात में नहीं होता, जब तक समानता का समाज कायम नहीं हो सकता है और प्रायः बिल बहुत साहब समाज में समानता साने के बहुत एजकोक्ट है। इसलिए मैं प्रायः के विवेक कसंगा कि हमारे बड़े को भी प्रायः सभों। सैकड़ों में 80 प्रायः के प्रथम कुर्सी से श्रमण कर दिया जाए,

सो समानता का समाज नहीं बन सकता चाहे वह बिहार हो, चाहे बंगाल हो और चाहे वह हरियाणा हो या काश्मीर हो। इस बात को ध्यान समझिये। तभी समाज में समानता स्थापित होगी और हम यह समझते हैं कि जैसा हमारा भाषण हुआ, वैसे ही ध्यान भी सम्पूर्ण और जोशीला भाषण देंगे और इस में ध्यान सब हमारा साथ देंगे।

इन शब्दों के साथ मैं अपना विधेयक पेश करता हूँ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

"That the Bill further to amend the Constitution of India, be taken into consideration."

Mr. Lakkappa.

SHRI K. LAKKAPPA (Tumkur): Mr. Deputy Speaker, Sir, I have gone through the entire Bill. I cannot agree with all the provisions of the Bill which have been slated down in it because some of the provisions would give rise to legal complications and controversies. My hon. friend has put forth his idea with a social objective in the statement of objects and reasons:

"The present Indian social structure based on Casteism and Brahminism has mentally and physically crippled a majority of our population."

Let us not attack any particular caste while discussing this Bill. We have to attack the whole caste system. There is no such thing as the domination of Brahmins or Rajputs or Jats or any one community. We must oppose the entire system of Casteism, wherever it prevails. Within the framework of the society that we have adopted in our Constitution, there should be a structural change, socio-economic change in our country in a democratic manner. A lot of changes are necessary. Although our Constitution envisages the social system, we have not yet achieved that goal. Our society has not developed as fast as we desire. That is where, the Members of Parliament, from this side as well as that side, are educating the people about their rights and privileges.

My hon. friend, the mover of the Bill, is from Bihar. I would say that

Bihar is a caste-ridden State. In every State, the casteism is there. Casteism can be controlled provided it is controlled by a political will and political power. In addition to that, there is an economic power, the concentration of economic power in the hands of a few people. Therefore, the regrouping, the restructuring, of the society is very necessary. The constitutional changes alone will not be enough. It is very necessary to see that socio-economic changes are supported by the political will, the political power of the State.

It has been rightly said that there is a monopoly of political power or the tentacles of political power in the hands of a caste-ridden society or a group of caste people or a dominating economic class, like, Birlas and Tatas. Even though they are in a minority, even though Birla-Tata group of industrialists are in a minority, they have got the economic power; there is a concentration of economic power in the hands of a few people. They are controlling not only the economic growth of this country but they are also controlling the gainful employment.

Take, for example, the Birlas today. The Birla-group industrial houses start industries and they control the entire system of Government machinery through which they generate employment and through which they spread their own kith and kin. For instance, there is the Hindustan Motors. They alone employ more than 4000 people belonging to the Birla families. This is what is happening. It is so even in the case of ancillary units. I read an article in a newspaper where it was stated that 400 families belonging to the Birla group are controlling the raw material and the ancillaries around big industries. All appointments right from the lowest, the chaprasis, to the highest level have been given to their own families. Where is the guarantee under article 18 or under the provisions of the Constitution for any citizen of this country to get jobs?

[Shri K. Lakkappa]

Today, an explosive situation of unemployment problem is there and it is mounting up. Last time, I brought forward a Bill on the Employment Guarantee Scheme in order to create confidence in the minds of the younger generation of people. But the reply given by the hon. Labour Minister, Shri Ravindra Varma, was that even the registers of Employment Exchanges did not give the correct number of unemployed people, literate or illiterate, skilled or unskilled, graduates or undergraduates, in this country. This is the situation prevailing in the country today.

Certain socio-economic changes are very necessary. I do not know whether the present Government is capable of bringing about any meaningful changes let alone how the democratic system has been set up. The other day, my hon. friend, the Industry Minister, Mr. George Fernandes, reeled out certain figures. I do not know how the figures have been prepared. He said that there is 8 per cent growth in industry. He has also said that they are bringing meaningful employment and other changes by introducing small scale industries, development of khadi and all those things. But I do not see any changes in this country; I have not seen any changes in the country in the last two years. Why is my hon friend not asking the present Government to bring about these changes? I do not know to which unit of the Janata Party he belongs, whether Jana Sangh or Swatantra or any other unit. Will he bring political pressure and political compulsions on the entire Party and see that meaningful changes are brought about by the present Government? But I know that the Janata Government is not for any of these changes in the society; they are not for breaking the monopoly of the monopoly houses. They are only regrouping the industrialists. They are bringing the multi-nationals from West Germany and other countries and are regrouping them because they are milk-yielding cows for them, they grease their palms. Therefore, how

can you expect any changes from the present Government? I want my hon. friend to revolt from the Party. I know, the Janata Party is not for making any of these social changes. What has happened in the last two years? Have they brought any changes in the society? Have they brought any revolutionary methods to protect the backward communities and other weaker sections of the society and to make them feel secure? (*Interruptions*)

AN HON. MEMBER: What is your philosophy?

SHRI K. LAKKAPPA: What is your philosophy, I want to know. Are you defending this Government? In Karnataka we have brought meaningful changes, we have implemented the 20-point programme, we have brought about many changes. We have created the consciousness among the backward classes to fight for their rights. We have brought about revolutionary changes even in the social system. Where a person has an annual income of Rs. 4,000 he will get not only land but also interest-free loans; and those people whose annual income is less than Rs. 4,000, they need not pay back to the money-lenders. We have done this to break the backbone of the money-lenders. We have also abolished the bonded-labour system. (*Interruptions*) What is your policy in West Bengal? Have the 'Communists', the 'Progressives', made any changes there? We have introduced land reforms in Karnataka. It may not be a hundred per cent.

But you have not even started? You have not done even one per cent. You only make slogans. You capture innocent people and parade them in the streets. Is it bringing socialism? You ask Mr. Saugata Roy. Was there any change in West Bengal? All those people who agitated for various changes were kept in the lock-up. And you are challenging Karnataka! We have done something in Karnataka. You better try to copy us. Ask Mr. Jyoti Basu to come to Karnataka and see. You must bring about the necessary changes in the society. It is

no use only criticising the vokkaligas or lingayats or any other community. But you must abolish casteism and you must bring in meaningful social reform measures.

16 hrs.

I welcome this but unfortunately the provisions have to be changed. I do not know how it will stand the legal test. However, the idea which is introduced in this is welcome. I want that the society should be changed also. Socio-economic changes are very necessary. Today, especially as far as the unemployment problem is concerned, the present Government has not been able to bring any changes in the last two years. We have been observing that. We know there are people on the other side who are conscious of the need of changes in the society and they believe in socio-economic changes. You must give guarantee of employment to the unemployed youth. Otherwise they will rise in revolt against the present government and if any member on that side would bring forward any measure with a meaningful change, we will all support it.

Sir, anyway, I welcome the Bill of the hon. Member.

डा० रत्नजी सिंह (भागलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य श्री विनायक प्रसाद यादव ने जो संशोधन विधेयक उपस्थित किया है। उसकी भावना बहुत ही उदात्त है। सचमुच में भारतवर्ष और खास कर हिन्दू समाज का प्रगर सबसे बड़ा दोष है तो वह जाती व्यवस्था है। यह ठीक है कि जिस जाति व्यवस्था को हम इनना दोष देते हैं, उनके मूल में वही व्यवस्था है और जैसा वेद में बताया गया है :-

ब्राह्मणोऽस्य मुखं प्रासीत्,
बाहू राजन्यः कृतः
तद्वरुच्यैः
पदभ्यां शूद्रोऽभजायत् ॥

वेद में जो वर्ण व्यवस्था कही गई है, उसमें जाति व्यवस्था कही नहीं है। इसलिये गीता में भी जब भगवान ने कहा है:-

चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं कर्मविभाषणम्
तस्य कर्तारमपि मां विद्धि कर्तारं वयं ।

हिन्दू समाज का जो संसार बड़ा मन्थ है प्रामाणिक मनु स्मृति, उसमें भी जाति व्यवस्था नहीं है, वहा भी क्षत्रिय के कर्म हैं, ब्राह्मण के कर्म हैं, तो कर्मणा जाति, लेकिन यहाँ तो जन्मना जाति है । इसलिये यह वर्ण व्यवस्था भारतवर्ष में नहीं है, प्राची वर्ण

व्यवस्था है। इसलिये इस वर्ण व्यवस्था को जितना जोड़ हम समाप्त कर सकें, वह अच्छा होगा।

16.03 hrs

[SHRI N. K. SHEJWALKAR in the Chair.]

यह बात ठीक है कि प्राज हमें इसके सम्बन्ध में जब सोचना चाहिये कि कैसे समाज को उठा सकते हैं तो बाइबल की एक कहानी है:-

Upto the last.

जो पीछे है, उसको ऊपर धाना चाहिये। गांधी जी ने भी अन्त्योदय से सर्वोदय की राहशात करन के लिये कहा। यह सही बात है कि भारत का जब संविधान बनने लगा था, तो हरिजन प्राविद्यालयों को संरक्षण दिया गया था। लोग कहते हैं कुछ दिन बाद पिछड़ी जाति के लोगों को भी संरक्षण देने की बात बर्ला और करीब 9 प्रांतों में तो उन्हें संरक्षण दिया गया है। लोग इससे उत्तेजित हो जाते हैं और कहते हैं कि यह संरक्षण क्यों, क्या यह समाजवाद के खिलाफ नहीं है।

हमारे श्री जेटमलानी जी संविधान के ज्ञाता हैं, वह बुरस्त कह सकते हैं कि भारत के संविधान की धारा 14, जिसमें सब को समान अवसर है, इसके खिलाफ है, लेकिन मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि सचमुच में समाजवाद और समान अवसर किस के लिये? प्रो. हेराल्ड लास्की ने कहा था:-

"To talk of equality between un-equals is unjust."

इस लिए समाज में जो असमान हैं, उनके लिए समान अवसर की बात करना गलत होगा। इस समाज पर, डिज समाज पर, माननीय सदस्य, श्री यादव, का इतना प्रायोग है। मैं समझता हूँ कि वह प्रायोग हमें सहना चाहिए।

प्राज रिजर्वेशन की बात चल रही है, लेकिन भारतवर्ष में पांच हजार वर्ष से रिजर्वेशन रहा है। यह प्रलय बात है कि वह रिजर्वेशन कुछ खास वर्गों के लिए था। भारत का इतिहास इस बात का साक्षी है कि ब्राह्मण संघी और क्षत्रिय राजा हुधा करता था। एक दो अपवादों को छोड़ कर—जैसे, चन्द्रगुप्त और छत्रपति शिवाजी महाराज को छोड़ कर—यही व्यवस्था रही। प्रायोग करने से काम नहीं चलेगा। लोग कहते हैं कि अगर हम ऐसे पिछड़े हुए और अयोग्य लोगों को अधिकार दे देते हैं, तो शायद वे सब कुछ नष्ट कर देंगे। लेकिन चन्द्रगुप्त को अवसर मिला, और यह सिद्ध हो गया कि भारतवर्ष के इतिहास में इतना कुशल शासन कोई नहीं था। छत्रपति शिवाजी महाराज को उनके राज्याभिषेक के अवसर पर प्रायोगिक देने के लिए कोई ब्राह्मण नहीं मिला। उन्होंने मयूर रामदास से प्रायोगिक मिला। इतिहास में उनका अपूर्व स्थान है।

जब ब्रिटिश वादसराय ने डा. भीमराव अम्बेडकर से पूछा कि प्रायोगिक क्या चाहिए, प्रायोगिक नहीं छोटी मोटी नौकरियाँ लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब प्रायोगिक हमारे लोगों को शीर्षस्थ स्थान देंगे, तो वे हमारे लोगों पर होने वाले अन्याय को रोक सकेंगे। इसी लिए डा. अम्बेडकर जिस स्थान पर थे, अगर वह

[६० रामजी सिंह]

वहाँ पर न रहते, तो शायद हरिजन और धार्मिकवासी उत्तम न बढ़ सकते, जितना कि वे बढ़ सके हैं।

जहाँ तक आरक्षण का सम्बन्ध है, अगर हम सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण से विचार करें, तो अल्पसंख्यक से ही सर्वोत्तम का प्रारम्भ होता है। अभी मैंने बाइबल का पत्र पढ़ाया है प्रमट विनास्ट। अगर हम समाजवाद के दृष्टिकोण से विचार करते हैं, तो हमें इस बात को मानना चाहिए कि विनास्ट काफ़ी ईक्वैलिटी बिटवीन प्रोटेक्टेड इज अनजस्ट। इसी लिए डॉ० राम मनोहर लोहिया न स्पष्ट कहा था कि जो समाज में दबे हुए और पिछड़े हुए लोग हैं, उनके लिए विशेष ध्वंस का मिद्वान्त होना चाहिए।

हमारे सचिवालय के निमित्तान्ना ने सचिवालय में यह व्यवस्था की कि जो सामाजिक और नैतिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जो सोशली एडजुकेशनली बैकवर्ड हैं, उनको रिजर्वेशन दिया जाये, और हम बात की जाय कि जो पिछड़े हैं कि कौन सा सोशली एडजुकेशनली बैकवर्ड है। हम के फनक्शनल काका कालेक्टर की अध्यक्षता में बैकवर्ड क्लॉसिज कमीशन बनाया। जब बिहार में फावर्ड और बैकवर्ड की धर्म-विभागीय जमीनी, तो मैंने उनसे मिल कर पूछा कि बिहार धर्म में जल रहा है उनके बारे में आप क्या कहते हैं। उन्होंने बड़े दर्द से कहा कि मैंने बीस वर्ष पहले जो रिपोर्ट दी थी, उसको आप लोगो ने कार्यान्वित नहीं किया, अगर उनका कार्यान्वयन कर लिया होता, तो इन बातों की आवश्यकता न पड़ती, लेकिन मैं किम को दाब दूँ किसको न दूँ ?

उस बैकवर्ड क्लॉसिज कमीशन की रिपोर्ट पर सबसे से शायद बहस हुई, लेकिन उसकी किसी भी सिफारिश का कार्यान्वयन नहीं हुआ। इसलिए पिछड़े हुए और दबे हुए लोगो को दिली में जो भावना है कि उन्हें न्याय नहीं दिया गया है, वह सही भावना है।

आज हम केवल नौकरियों में रिजर्वेशन की बात करते हैं। नौकरी कितने परसेंट लोगों को मिलती है ? काका साहब कालेक्टर ने दो वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद अपनी रीकमेन्डेशन दी थी। उन्होंने कहा था कि हमें विचारना चाहिए कि जो बर्बो, उपेक्षित, पद-दलित मानवता है, हम उसको हटाएँ कि नहीं—सामाजिक, धार्मिक और राजनैतिक क्षेत्र में—कैसे उठा सकें। लेकिन हम लोगो ने कोई ध्यान नहीं दिया और आज केवल सर्विसेज की बात होती है। सर्विसेज के बाद मैं उन्होंने सामाजिक रूप से भी विचार किया था और कहा था कि यह सिद्धांत गलत है।

"I am definitely against reservation in government services for any community for the simple reason that the services are not meant for the servants but they are meant for the service of the society as a

whole. Administration must have the service of the best men available in the land and these must be found in all communities. Reservation of posts for certain backward communities would be as strange as reservation of patients for particular doctors. The patients are not meant to supply adequate or proportionate clientele to all the doctors whatever their qualifications."

लेकिन हम के बावजूद भी उन्होंने मारी अनुसूची की है और कहा है कि 49 प्रतिशत तक हो सकता है। केवल नौकरियों की ही बात नहीं है हम तो केवल एक पक्ष लेते हैं। उन्होंने जब यह कहा कि कौन बैकवर्ड और कौन फावर्ड है, हम का प्राहटीरिया क्या है, तो उस के उन्होंने 15 मापदण्ड बनाए हैं। लोग कह देंगे कि यह तो बैकवर्ड बनाम बी बात है। वैज्ञानिक हम से उन्होंने दिया है कि पिछड़ा कौन है ? सचमुच में प्रायः सैड्युलर कास्ट में और बैकवर्ड क्लास में कोई धर्म बड़ा समूह शिक्षा और धर्म में हो गया है और वह धर्म मरक्षण मानना है तो समाजवाद के मारे सिद्धांत का यह इनका काम है। ये पन्द्रह मापदण्ड उन्होंने बनाए हैं—बैकवर्ड कौन है—बीनेन, औरत बैकवर्ड है और पुरुष फावर्ड है। प्राचीन क्षेत्र में जो है वह बैकवर्ड और शहरी क्षेत्र में जो है वह फावर्ड। अपने प्रायः के काम करने वाले बैकवर्ड और केवल मुद्रवाङ्मय करने वाले जो हैं वह हैं फावर्ड।

Those labouring under the sun and the open air are backward

में साग नहीं पड़ता। इस तरह में 15 प्राहटीरिया उन्होंने बताए हैं। ये पन्द्रह जो मापदण्ड हैं इनकी कसौटी पर डाल कर के उन्होंने निर्णय लिया था। इसीलिए उन के सिद्धांत को, उन की अनुसूचान्ना की अगर हमारी पिछली सरकार ने नहीं माना है तो यह बड़ा दोष है। सचमुच में कोई मनासत काल के लिए इस सरकार की माय नहीं की गई थी। यानी जो दबे हुए हैं, उन को बोधी दर तक हम सहारा दे कर उठा देते हैं ताकि सब के बराबर धारा जाय, सब प्राहटिकल 14 जो इक्वेलिटी का सिद्धांत है वह चलेगा। जब तक वह दबे हुए हैं जब तक विशेष ध्वंस प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देना, यही समाजवाद का और जनतंत्र का लक्ष्य है। यही कारण है कि उस समय जब यह शुरू हुआ था तो बिजनेस में तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में, आन्ध्र में और महाराष्ट्र में भी यह सब रिजर्वेशन उनी समय में है। हमारा एक लक्ष्य है बीनेन क्लॉसिज की की पार्टी में। नम्बरीपाद की जब बिहार में आए थे तो उस ने कहा कि रिजर्वेशन के पर में आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं हैं ? तो उन्होंने कहा कि यह जो रिजर्वेशन के बिनापक हस्ता हो रहा है

This is a mass hysteria. Neither you can check it nor can I. Therefore, I did it in Kerala 20 years ago but

this hardly solves 1 per cent of the unemployment problem.

घोर इसीलिए आज मैं यह कहना चाहूंगा कि यह रिजर्वेशन की बात हम आज करने हैं, लेकिन जिन देश में 70 प्रतिशत प्रायमी गरीबी की देखा के नीचे है और 13 करोड़ प्रायमी जहा बेकार है वहाँ आज डिमांड ठोनी बाह्य राइट टू वर्क की और अब इस तरह की बात होगी ता यह भी बात हो जायगी। बिहार की सरकार चार हजार नीकरिया मान में होगी, उस से चार हजार लोग घ्राये जा जायगे। हमें ता यह पायनपन लगता है क्योंकि सचमुच में आज अगर जो फारवर्ड है वह यह समझने हैं कि पांच हजार लोगों की हमारी सर्वायल खत्म हो रही है और बैकवर्ड समझते हैं कि कुबेर का सारा खजाना और लक्ष्मी और विष्णु का सारा बैमव हमें मिलने वाला है तो यह ठीक नहीं है। सचमुच में मांग करना हा तो यह ता ठीक है समाजवाद के दृष्टिकोण में और जनतक दृष्टिकोण स कि पिछड़े लोगों का विनाश घवसर मिलना चाहिए, लेकिन हमके नाच यह मांग हुनी चाहिए कि हमको राइट टू वर्क दिया जाए ताकि गरीबों और अराजगारों मिट सक।

जहाँ तक कुछ लोगा ना नोकरों दे देने की बात है, उन दिन अब मारी बात हा रहे थी तो घटवजी ने जो कहा वा कविता के टय व कह बड़ा मार्मिक लगा—उन्हेने कहा कि मेरा रिट्टी मेन्केरी पिपडी जात का है तीन हजार रुपय कमाना है उनके लडके को तो रिजर्वेशन मिल जायगा तकिन मेरा चगरसी जोकि ब्राह्मण हैं उसके लडके को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। (स्वच्छासन)

श्री महीशाल (बिजनौर) डा राजेन्द्र प्रसाद जी ने बपरासी के लडके के पेर छुा दे और दक्षिणा भी दी थी (स्वच्छासन)

डा० रामजी सिंह यही कारण है कि महाराष्ट्र में श्री एस एम. जाशी के बात करने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने वार्षिक बजट्टीरिया रखा। इस दश में तथाकथित पिछड़ी जाति के कहलाने वालों में भी सुखी, सम्पन्न और समूह लोग भी हैं और दूसरी धोर लगे, कुबले और गरीब लोग भी हैं जोकि इससे बचित रह जायेंगे। (स्वच्छासन)

इसलिए हमें इस बात पर काफी जाति से विचार करना चाहिए। हम अपनी सरकार को धन्यवाद देते हैं कि जहाँ काका कानेलकर कमीशन की रिपोर्ट को लोगों ने रही की टोकरती में फेंक कर दिवों को दुखी किया वा, प्रापने नया बकबडे क्लासेज कमीशन का बटन किया क्योंकि सचिवालय में इस बात का प्रावधान है कि कुछ वर्षों के बाद इसकी जांच होनी चाहिए की स्थिति में क्या सुधार हुआ है, क्या बचभाव

घाया है। यह जांच कमीशन जांच करके जल्दी से जल्दी अपनी रिपोर्ट देगा। मुझे विश्वास है कि जो कमीशन बनाया गया है वह काका कानेलकर कमीशन की मेहनत का लाभ उठाएगा और बदली हुई परिस्थितियों में लोगों की जो प्रापानिया और कठिनाइयाँ हैं उन पर भी ध्यान देगा।

श्री बिहार में जो रिजर्वेशन की बात हुई, एक नए विचार से कुछ हुआ, वहाँ के मुख्य भरी घब ता मुख्य मंत्री नहीं रहे, वहा पर लोगों ने बडा धाकोष किया। मैं समझना हू सबसे ज्यादा रैशनल टग से बिहार में किया गया, अनेखर तन और अनेखर टू में घेद किया गया है, ना बडे हुए हैं उनका धोड़ा रकना चाहिए और जो ज्यादा बने हुए हैं उनको सहायता मिलनी चाहिए। 12 परसेंट अनेखर टू के लिए है और 8 परसेंट अनेखर वन के लिए है। इनके माथ ही जा तथाकथित उल्ख जाति के लोग हैं, उनमें जा बीकर सेकास है, उनको भी 3 परसेंट है और महिलाओं के लिए भी है। जहाँ तक समाजवाद की बात है और किमी के लिए कुछ कहा जा सकता है लेकिन डा लोहिया के समाजवाद की सम्बाई पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। डा लोहिया न 60 और 40 परसेंट की बात कही थी जिसमें उन्कोन हरिजन, धार्मिकी, पिछड़ी जाति, गरीब मयलमान, सभी का रखा वा। कुछ लोगों ने कहा कि प्राप 60 परसेंट द रहे हैं तो उन्कोने उत्तर दिया कि देना ता चाहिए 90 परसेंट, सभी ता में 60 परसेंट की बात कर रहा हू। इसीलिए मैं इस प्रस्ताव की भावना के बिल्कुल माथ हू और मैं सरकार से प्रायह कम्मा कि वह रिपॉर्ट जल्दी से जल्दी प्रकाशित हा करे और और उस नये बैजानिक परिस्थय में, नई जानकारी के धाराक में हम एक सिफारिश दें और केवल एक सिफारिश ही न दे, बल्कि उस का हम कार्यान्वित करे।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हू।

*SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER (Durgapur): Mr. Chairman Sir, I rise to take part in the discussion on the Constitution Amendment Bill introduced by Shri Yadav which seeks to amend article 16 of the Constitution. In this connection, I would like to say that while discussing the Bill we have to discuss the social and political situations that are prevailing in the country, as without it the discussion would be meaningless. If we look to the rural areas, we will find that ownership of land is concentrated in a few hands in the sphere of industries, only a few monopoly

*The original speech was delivered in Bengali.

[Shri K. C. Halder]

houses run by a few families are having a stranglehold over the means of industrial production and we are made to live in a society which is fragmented in different classes. And because of these, different socio-economic problems are growing. In the present economic set up nearly 60 to 70 per cent of the population is living below the poverty line, the income disparity between one class of people and another is growing and the disparity in income is also growing side by side. Needless to say, Sir, the total cumulative effect of all these disparities has contributed to the ever increasing number of unemployed people in our country. We all know that provisions for reservation of posts in the services have been made for the members of the scheduled castes and scheduled tribes people in our Constitution. But the prevalence of the capitalist economy not only in India but all over the world has created such disparities that problems of the people who are at the lower strata of the society have multiplied manifold and it is but natural that the minority Muslims today are voicing their grievance to say aloud that they are not being given a fair deal. Similarly the Christians too are saying that justice is not being done to them. Demands are being made for prescribing suitable reservation for the different classes. It is a problem which has to be dealt with urgently but while trying to do so we have to go into the root of the problem and should try to eradicate it from its roots as otherwise any piecemeal, ad hoc or superficial approach cannot bring about any permanent solution of the problem. Sir, the Janata Party has given a promise to the nation that through Khadi Gram Udyog, Cottage industries and small scale industries which we support, they would be able to eradicate unemployment from this country within the next 10 years. But as long as the capitalist structure of the society is retained, and as long as the class character of the society is retained

by the vested interest the people in the villages and cities will continue to be oppressed and victimised and mere pious wishes of the Janata Party will be of no help to the millions of the exploited and oppressed masses of our country. What is really needed is a structural change of our society unless this is done we can never be near to our goal and as I had said in the last Lok Sabha even during this Lok Sabha and as has been suggested by Dr. Ramji Singh, it is necessary to give to every youth of our country a right to work. Every young man who wants to work should be given work and this can be done only by amending the Constitution and making right to work a fundamental right. Unless this is done, the problem will grow and become complex and still more complex day by day. More and more demands will be made from the different sections of the society and if it is not tackled in a major way, then I am afraid the integration and unity of the nation will be in jeopardy. Therefore I will caution the House and appeal to the members, and particularly the Government that they should not wait any longer. Dr. Ramji Singh may recommend a total revolution but as long as the capitalistic structures of the society continue, as long as a few capitalist will continue to control the means of production as long as the foreign money continue to have a lion's share of our economy and their profits are repatriated to foreign countries we would never be able to eradicate the evil that the present Bill seeks to do. Therefore, I would like to suggest that in order to achieve our goal we should immediately address ourselves to the task of replacing the present capitalistic economic structure of the society and restructure on a national basis where the welfare of the masses and the exploited millions will have a priority over the welfare and wellbeing of a wealthy few. Secondly, I will suggest that the means of production should be socialised. This by itself will eliminate the formation of pri-

vate capital and the exploitation by a few and depriving the millions. Thirdly, it is absolutely necessary that the concept of personal profit should be done away with. Once it is done, then the all that will be produced will belong to the society and its people. All the profits will be invested not for the welfare and wellbeing of a few wealthy families and classes but will be shared equally by the poor who produce the wealth today but have not proper share of the profit. As soon as socialisation of the means of production is done, the profit will be invested for the developmental work, and it will generate more cottage and small scale and other industries will thus help us to eradicate the bane of unemployment from our country. Thus we have to strike at the root of the evil and unless we are bold enough or courageous enough to do it, we will go round and round the vicious circle without knowing how to come out of it. I also feel that a piece meal approach to the problem will not yield any result either. Let me make it very clear Sir that my party the CPI (M) supports and will continue to support all justiable demands of the oppressed and exploited sections of the society, the demands of the members of the scheduled castes and scheduled tribes people, the demands of the Muslims, Christians and other minority communities of our country but I will tell them all that we should not approach the problem from a narrow communal angle. If we commit that folly we would never be able to solve the problem. Therefore, I would give a call to one and all to all those who are interested in the welfare of the country, and say gentleman let us unite—let us put an end to total exploitation that is now rampant in our capitalist society, let us work together to unite and consolidate all those who are lagging far behind in the race of social and economic progress, and let us all together give rise to a society which will be free from exploitation and oppression. Ours is an agricultural country and

the development of agriculture will naturally form the core of any plan that will seek to help the poor. A proper development of agriculture will depend on a proper distribution of land to the landless and liquidating the present concentration of land in a few hands. We have therefore to legislate and implement a proper land reform procedure which will bring an end to feudal exploitation in the rural areas. This will further enhance the purchasing capacity of the poor, will give birth to more and more industries, both cottage and small, and will provide more employment to the people. If we are able to do this we would be able to create a new society—so very different from the present one—where exploitation will be a forgotten word, where one class will not be pampered at the cost of the other, where the members of the scheduled castes and scheduled tribes will not be treated worse than animals and where the Muslims and the Christians will not suffer from agonising feeling of being given the treatment of a second class citizen. We have to initiate a class struggle through which we would be able to generate an atmosphere of total revolution and proceeding through this path we would no doubt be able to bring about a revolutionary change in our society which will not patronise exploitation, will generate wealth through socialisation of the means of production, will usher in an era of happiness and prosperity for all. It would be society where education and medical facilities will be catered to all free of cost and which will guarantee job to the job seeker. This we can do only by a united and unified approach, by eschewing narrow communal feeling and by organising the exploited and the havenots. If we are able to do it, we would be one of the strongest and the mightiest nation of the world. I thank you Sir, for giving me the opportunity to express my views on this matter.

श्रीमती इन्दिरा प्रियदर्शिनी (श्रीमती इन्दिरा प्रियदर्शिनी) : रिज-
वैसन का बड़ा मायक मानना है। रिजवैसन से जिन
लोगों ने फायदा उठाया है वे उस फायदे के मुन्दाहिक

[बीधरी बसबीर सिंह]

नहीं थे। आज उन लोगों को रिजर्वेशन से फायदा पहुंच रहा है जिनकी हालत अच्छी है, का खुद आई०ए०एस० में है। उनके बेटे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। उनके पास पूरे पैसे हैं और हर किस्म की उनकी सुविधायें मिली हुई हैं। इससे मैं समझता हूँ कि संरक्षण का रिजर्वेशन का जो मकसद था वह मारे का सारा खर्च हो जाता है और हो गया है। सरभण उनकी मिलना चाहिये जिनके पास साधन नहीं हैं, जो सामाजिक और पर पिछड़े हुए हैं, पढ़ाई लिखाई के मामले में पिछड़े हुए हैं, जो प्राथिक और पर पिछड़े हुए हैं। जो अच्छे-अच्छे पदों पर बैठे हुए हैं उनका धारक्षण का लाभ क्यों मिले? फायदा हमका उनको पहुंचना चाहिये जो इसके मुनाफिक हैं, जिनको हमकी जरूरत है जिनका समाज में मकाम ठीक नहीं है। जिनके लिए रिजर्वेशन रखा गया था उनको इससे फायदा नहीं पहुंच रहा है। वे बेकार उमी तरफ से बैठे हुए हैं। कोई बन्धत था जब समाज में उनका कम्युटीशन करने का मौका नहीं मिलना था, उनको हक नहीं था कि वे या औरने पढ़ लिख सकें, समाज में बहुत से लोग थे जिनका वेद पहुंचने का अधिकार नहीं था। स्वामी दयानन्द ने और धार्मिक समाज में इसके बारे में बहुत बड़ा काम किया है। उन्होंने कहा है कि हर धार्मिक का हक है कि वह बह सके, उस कोई रकाबत नहीं धरनी चाहिये। महाभारत का किस्सा धारके मामले में। एकलव्य जब द्रोणाचार्य के पास जाता है और बतला है कि मुझे शिक्षा दो, तो उन्होंने कहा कि धारका शिक्षा का अधिकार नहीं है, धारका शरत् और भरत् विद्या सीखने का अधिकार नहीं है, क्योंकि धार उस जाति से है जिनका मैं पढ़ा नहीं सकता हूँ। तो उस समय समाज में एक व्यवस्था थी, कुछ लोगों के लिये बाँदा था, वह समाज में कुछ लोगों के मुकाबले में नहीं था सक्ने थे। आज जरूरत है रंग बात की कि जिनके लिये साधन नहीं हैं उन्हें सुविधाएँ दी जायें।

एक गाँव में गरीब धार्मिक काम करता है, चाहे वह हरिजन है या किसान है। उसके पास साधन नहीं है। जब लड़का स्कूल से घर आता है तो घर पर मा-बाप कहते हैं कि बिल से धाधा, उन्हें पानी पिला लाओ और इनके लिये घास काट कर ले आओ। दूसरी तरफ जब हरिजन का बच्चा आता है तो उसके घर वाले उस बच्चे को अपने साथ काम के लिये ले जाते हैं। दूसरी तरफ वे लोग हैं जो खुद पढ़े हुए हैं, घर में बीबी पढ़ी हुई हैं और उनका बच्चा भी अच्छे कान्वेंट स्कूल में पढ़ने के लिये जाता है। जब वह बच्चा घर आता है तो उसे हर किस्म की सुविधाएँ और साधन मिलते हैं। तो इन अच्छे साधन-सुलभ बच्चों के मुकाबले में वह बच्चे नहीं धा सकते हैं, जिनके पास कोई सुविधा या साधन उपलब्ध नहीं है। उन लोगों के लिये आज जरूरत है कि हम उनके लिये कोई धारक्षण करें। हम उन लोगों के लिये इस किस्म की सुविधायें दें कि वह उनके मुकाबले में धा सकें जिनको सारी सुविधायें मिली हुई हैं। उनका, वह बच्चे किसी भी जगह मुकाबला कर सकें। लेकिन आज इसके उलट बात होती है। धार जिनके लिये हमने यह रिजर्वेशन रखा है, उनको तो फायदा नहीं पहुंचता। अब एक

क्लास पैदा हो गई है, चाहे वह हरिजन है या बैकवर्ड क्लास है या दूसरी प्राथिकासी जाति के हैं, वह एक क्लास है और सिर्फ उस क्लास के लोगों को फायदा है, जहाँ को फायदा पहुंच रहा है। इसके लिये यह जरूरी है कि हम यह देखें कि जिन को साधन नहीं मिले हैं, समाज में सगातार पिछड़े रहे हैं, जिनका बोधन किया गया है उनको मबब दे। नौकरियों वगैरा की बात खर्च हो जाती है, अगर हम हर हाथ को काम दें।

जो विधेयक इन्होंने पेश किया है, वह एक महत्वपूर्ण धार है। अगर हम हर हाथ को काम दें, तो उसके लिये रेज्यूलेशन लाना चाहिये, अपने विधान में संशोधन करें कि हर धार्मिक का काम मिले और उसमें इतनी ज्यादा डिस्पीरटी न हो। हम कम-से-कम और ज्यादा-से-ज्यादा जहा तक हो मुकर्रर कर दें कि इतना मिलेगा। आज जो नौकरियों के लिये दौड़ है उसकी वजह यह है कि एक तरफ तो डेढ़ सी और 200 रुपये मिलते हैं और दूसरी तरफ हजारों और लाखों रुपये मिल रहे हैं। तो इस डिस्पीरटी के कारण भी लड़ाई है।

बाहर के देशों में जा जाने वाले हैं, वह जानते हैं कि वहा जो हाथ से मेहनत का काम करते हैं, उन्हें ज्यादा पैसा मिलना है। जा ब्लाइट कालर लोग हैं, उनको वहा कम पैसा मिलना है, लेकिन जा भूरी के धारों खड़े हाकर काम करते हैं, उनका ज्यादा पैसा मिलता है। पा दपतर में एयर-कंडीशनिंग वे जाकर बैठते हैं कागज का काम करते हैं, उन्हें कम मिलता है और जो बाहर काम करते हैं उनका ज्यादा मिलता है। आज जो पूजीपति देव है, वहा दूसरी व्यवस्था है। वहा हाथ से मेहनत करने वाले की इज्जत है, लेकिन वहा हाथ से मेहनत करने वाले की इज्जत नहीं है। जो सफाई का काम करता है, उसे पैसा भी कम है, समाज में सम्मान भी कम है। जो धार्मिक कोई काम नहीं करता, दपतर में पछे के नीचे बैठा कागज देखता रहता है, उसे वहा ज्यादा पैसा मिलता है और मान भी ज्यादा है। असा डा० वामजी सिंह ने कहा है, आज सारे समाज के हाथों का बदलने की जरूरत है। हमें ऐसा हतबाम करना चाहिए कि काम करने वाले और मेहनत करके वाले के लिए समाज में इज्जत हो, उसका पैत धर रोटी और पहलने के लिए कपडा मिल सके। हर एक धार्मिक को काम मिले, और धार सरकार किसी का भी काम न दे सके, धो उसे बेकारी एलाउस दिया जाये। जिन देशों को पूजीवादी देव कहा जाता है, अगर वहा पर हिन्दुस्तान से गये किसी धार्मिक को इमीग्रेशन का पर्चा मिल जाये और वहा ठहरने का हक मिल जाये, और अगर वह धार्मिक, जिसका वहा की धरती और वहा के समाज से कोई तास्लुक नहीं है, जिसका रंग और मस्ल वहा के लोगों से भलस्य है, वहा एम्प्लायमेंट एक्सचेंज में अपना नाम लिखाता है, तो 48 घंटों में काम न मिलने पर सरकार उसे बेकारी एलाउस देती है। थिय धार्मिक का उस देश से कोई तास्लुक नहीं है, जो उस देश का ही नहीं है, लेकिन अगर उसे एक पर्चा मिल जाये कि वह देश में ठहर सकता है, तो उसे काम करने का हक मिल जाता है।

अगर हमारे देश में भी हर हाथ को काम मिले, तो वह रिजर्वेशन बगैरह का सब बककर बरत हो जाता है। जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में भी हमने कहा था कि हम हर हाथ को काम देंगे।

इस देश की धरती में हर एक चीज मौजूद है। यहाँ पानी है, कमीन भण्डी है, हर किसम का मौसम है, हर चीज पैदा होती है। जब यहाँ पर काम करने वाले हाथ हैं, काम करने वाले विभाग मौजूद हैं और दौलत देने वाले धरती है, तो फिर हमारे देश में कमी क्या है? —कमी है सिर्फ आर्थोनाइजेशन की, तरतीब की और हमारे सरकार की। अगर हमारा सरकार हो, तो हम हर आदमी को काम दे सकते हैं और आदमी को उसकी जरूरत के मुताबिक दे सकते हैं। इस तरह हमारा हर आदमीवैस को तामीर म जुट जायेगा।

जहाँ तक रिजर्वेशन का सवाल है, बहुत से लोगों को उसकी बजह से बिला-बजह फायदा हो रहा है। सरकार यह तय कर बै कि जिन लोगों के धार्मिक, सामाजिक और शैक्षिक—इकनामिक सामान्य और एजुकेशनल—हालान प्रबन्ध हो चुके हैं वे लोग इससे फायदा न उठा सकें और जिन लोगों के पास ये सब सुविधायें नहीं हैं, उनका इस से फायदा मिल सके। अगर एसा इन्तजाम हो जायें, तो हमारा गमाज धागे बंद मकंगा, देश तरक्की कर सकेगा।

श्री राम बिलास पासवान (राजपुर) सभापति महोदय, मैं एक कहानी से अपना भाषण शुरू करता हू। हमारे धर्म-धर्मों में कहा है कि जब देवताओं और दानवा का गूढ़ दुश्म था, तब समुद्र-मन्थन किया गया था। उसके लिये पहाड़ को मथानों और नाग को रस्सी बनाया गया था। मथान यह उठा कि नाग का मुह कौन पकड़-देवता पकड़े या दानव पकड़। देवताओं ने कहा कि हम लोग नाग का मुह पकड़ने वाले नहीं हैं, हम तो उसकी पुष्ट पकड़ेंगे। तब दानवों ने नाग का मूत्र पकड़ा और समुद्र-मन्थन हुआ। समुद्र में से हीरे, जवाहरात और नव रत्न निकले, और एक अमृत का थड़ा भी निकला। तब यह विवाद होने लगा कि अमृत कौन पियेगा। दानवा ने कहा कि कमाले वाला खायेगा, हम लोगों ने नाग का मुह पकड़ा है, अमृत का थड़ा हमें मिलना चाहिये। देवता यह नहीं चाहते थे, लेकिन वे यह बात सीधे कैसे कहें? तो उन्होंने कहा कि इसके लिये पंच-नर्गय कराया जाये। प्रथमन विष्णु ने माँहिनी, सुन्दरी, का रूप धारण किया, और उन्होंने कहा कि मैं जो बात कहूँगी, वह सब को माननी पड़ेगी। दानवों और देवताओं ने कहा कि ठीक है। माँहिनी मुस्कराती तो भी दानवों की तरफ देख कर, मग्न अमृत का थड़ा बढ़ाती थी देवताओं की तरफ। थड़ा इन तरह बढ़ते बढ़ते जब देवताओं की तरफ चला जा रहा था तो उस में एक दानव हाँसियाग था—राहु। राहु ने देखा कि यह तो सब थड़ा उधर ही बढ़ जायेगा तो उस ने क्या किया कि जब बल कर और देवता का रूप धारण कर देवताओं की ओरों में जा कर वह बैठ गया। जब कहाँ जा कर बैठ गया तो उस को भी अमृत मिल गया। जब उसने अमृत पी लिया तो वह तो अमर हो गया। देवताओं ने देखा कि एक दानव ने अमृत पी लिया है तो उन्होंने ने विष्णु भगवान से कहा कि यह तो दानव है, इस ने अमृत पी लिया। तब विष्णु भगवान अपने अश्वकी रूप में आ गए बक लिए हुए और बक से उस दानव की

गर्दन उन्होंने काट दी। तो उस के दो हिस्से हो गए जो राहु और केतु के नाम से आज तक चले आ रहे हैं। तो आज भी हम लोग राहु और केतु के नाम से विख्यात हैं। आज पाँच हजार वर्षों से और पिछले तीस वर्षों की कार्रवाई हुकूमत में यही स्थिति रही कि माँहिनी कभी सरकार मुस्कराती तो ही गरीबों की तरफ देख कर और उस का अमृत का थड़ा खूला हुआ बढ़े बढ़े लोगों के लिए, टाटा बिरला के लिए। यह बात अभी भी हम लोगों के दिमाग में न धावे, हमारी समझ में न धावे तो आश्चर्य की बात है।

हमारे नेता बलबीर सिंह जी बैठे हुए हैं। वह जानते हैं, हम लोग जिस स्कूल के विद्यार्थी हैं उस में हमेशा हमें यही पढ़ाया गया है कि ससोपा ने बाघी गाठ, पिछड़े पाए तो मैं लाठ।

इसके पहले रूप नाथ सिंह जी यादव का विम्वन भाक साशन टिसएबिलिटीज का बिल धाया था। उन्होंने तो हुबहू उसी लाइन पर अपना बिल रखा है कि 60 प्रतिशत स्थान पिछड़े लोगों के लिये प्राप सुरक्षित कीजिये। मैं प्रापको संविधान की तरफ ध्यान से बसता हूँ और मैं मयमाता हूँ कि माननीय गुरु पदवी जी पाटिल साहब स्वयं विद्वान और एक बहुत बड़े वकील हैं, वह जानते हैं, हम में कहीं इसक मांग में कोई रुकावट नहीं है। प्राप देखिये कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल 15(4) को, उस में लिखा हुआ है—

15(4) "Nothing in this article or in clause (2) of article 29 shall prevent the State from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes"

फिर प्राप आर्टिकल 16(4) की देखिए, उस में लिखा हुआ है—

16(4) "Nothing in this article shall prevent the State from making any provision for the reservation of appointment, or posts in favour of any backward class of citizens which, in the opinion of the State, is not adequately represented in the services under the State."

यह बिल्कुल स्पष्ट रूप से उस में दिया है। इनलिये यह जो तर्क दिया जाता है कि यह नहीं हो सकता, यह ठीक नहीं है। इस में दो चीजें सामने आती हैं। प्रथी कान्ता कालेकर कमेटी की रिपोर्ट की बात की गई। डाक्टर साहब ने उस के बारे में कहा। लेकिन मैं प्राप से कहना चाहता हूँ, मुझ को कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है कि जालवर के दो मुह होते हैं या साप को दो जीभ होती है लेकिन आदमी की भी दो जीभ होती हैं, यह पृथ्वी बार इस सभ में आने के बाद देख रहा हूँ। प्लुटुकी

[श्री राम बिलास पासवान]

प्रधान मंत्री श्रीमती इरिण गांधी हरिजनो के लिए रोज प्रांशु बहाती हैं लेकिन बिहार में जब कर्पूरी ठाकुर की सरकार ने कहा कि हम हरिजनो को हथियार देंगे, यह बेमेल लड़ाई नहीं चलने वाली है कि एक तरफ राक्षकल और बन्कू हो और दूसरी तरफ निहत्थे हरिजन हों, यह हम नहीं चलने वेग और बेमेल लड़ाई नहीं होगी, या तो दोनों को हथियार मिलेगा और नहीं तो दोनों के हथियार छीन लिये जायेंगे, तो श्रीमती इरिण गांधी का दूसरे दिन अखबारों में बयान था गया कि हरिजनो को हथियार देना गमत है—श्रीमती इरिण गांधी ।

श्री बीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) . दो मंह से बोलती हैं न ।

श्री राम बिलास पासवान दो जीम से ।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ । 1953 में 21 जनवरी को डा० राजेन्द्र प्रसाद जी जो उस समय के राष्ट्रपति थे उन्होंने काका कानेलकर की अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की । 1955 में काका कानेलकर आयोग में एक प्रपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और 1979 में हम लोग उस पर विचार करने के लिये बैठे हुए हैं । 55 में रिपोर्ट दी गई और 24 वर्ष बाद हम लागू किए बैठे हैं उस पर विचार करने के लिये । और फिर प्रधान मंत्री जी ने कह दिया कि हम दूसरा आयोग गठित करते हैं । अब दूसरे आयोग के अध्यक्ष हैं श्री निम्बेश्वरी प्रसाद मडल । 24 वर्ष तक इन का कार्यकाल चलेगा । दो वर्ष बाद यह रिपोर्ट प्रस्तुत कर देंगे और उस रिपोर्ट को खटाई में डाल दिया जायेगा । 24 वर्ष बाद तीसरे प्रधान मंत्री आयेगे, वह कह देंगे कि आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था में बहुत परिवर्तन आ गया है, इसलिए हम एक तीसरा आयोग गठित करते हैं । तो आप कमोशन के ऊपर ऐसा खर्च कीजिये, और बीजा पर खर्च कीजिये, लेकिन आप की नीयत कही साफ नहीं है ।

इसलिये मैंने कहा कि जब तक नीति और नीयत—दोनों साफ नहीं होगी शासन की तब तक देश का भला नहीं होगा । डाक्टर साहब न जो बात कही वह ठीक कही । जब जब हम देश का राजा उच्च जाति का रहा, मंत्री ब्राह्मण रहा तो वह स्वर्ण काल नहीं कहलाया । स्वर्ण काल तभी कहलाया जब बन्कूपल राजा हुए । छत्रपति शिवाजी का शासन सब से अच्छा माना गया । इसलिये यह कहना कि चूकि यह पिछड़े लोग हैं, इन को कोई प्रास्ट देंगे तो सन्तान नहीं पायेंगे—यह बिल्कुल गलत है । वर्तमान शासन की नीयत बिल्कुल साफ है इसलिये वह अपनी नीति को भी स्पष्ट कर दे ।

यहां पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया जाता है । मैं जनता पार्टी के मनीफेस्टो का हवाला देना चाहता हूँ । दो साल से अधिक हो गए हैं, अगर यह सम्भव नहीं था तो आप में जनता को बीच में क्यों इस की प्रकाशित किया ? मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ कृषि रजिस्ट्रेशन में थियराल रखने की बात है, अभी भी

यह लिये की हैं, राख नारायण जी हैं, मामा कालेश्वर दयाल हैं, क्यामनन्धन की निम्न हैं, जेठमलानी भी हैं—इस मामले में कही दो रायें नहीं हैं । इस देश का साम्राज्य रहा है कि पिछड़े लोगों की लड़ाई को जंचे कुल के लोगो ने ही लड़ी है । बहादुर काका कानेलकर की बहुत चर्चा की जाती है, मैं पंडित हैं, ब्राह्मण थे लेकिन उन्होंने अपनी रिपोर्ट बड़े स्पष्ट रूप में पेश की थी ।

जनता पार्टी ने अपने मनीफेस्टो में लिखा है :

“जनता पार्टी का मत है कि समाज के इन पिछड़े वर्गों तथा शिक्षा और सम्पत्तता की दृष्टि से उन्नत वर्गों के बीच जो खाई है उसको भीषणता से तभी पाटा जा सकता है जब कि पिछड़े वर्गों के लिये विशेष व्यवहार की नीति अपनाई जाये । अतएव पार्टी इन वर्गों की शिक्षा और रोजगार के विशेष सुयोग देगी । कालेलकर आयोग की सिफारिशों के अनुसार सरकारें नौकरियाँ में पिछड़े वर्गों के लिये 25 से लेकर 33 प्रतिशत तक नौकरियाँ सुरक्षित की जायेंगी । हरिजनो को मकान बनाने के लिये जमीन दी जायेगी ।”

अब सबाल उठता है क्या सरकार को यह पावर है कि वह 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण कर सके ? मैं मतिधान का विशेषज्ञ नहीं हूँ लेकिन जैना मैंने सविधान वा पदा और समझा है, उनके मुताबिक सविधानिक दृष्टिकोण से एस पर कोई रोक नहीं है । आप देखें कि 1971 की एक रुजिजग है सुप्रीम कोर्ट का आदेश प्रदेश के मध्य में, ए आर्द और, पेज 1710 पर आप देखें .

“That in adjusting the claim of both the weaker and the stronger elements, the reservation for the former should be ordinarily less than 50 per cent although no flexible percentage could be fixed and the actual reservation must depend upon the relevant prevailing circumstances in each case.”

इसमें भी बड़ी रोक नहीं लगी है कि आप 50 परसेंट से ज्यादा नहीं कर सकते हैं । इसलिए मैंने दो बातें कही हैं । आज इस देश में ऐसा मौका आ गया है जब कि आप पिछड़े लोगों को बहुत दिनों तक दबाए नहीं रख सकते हैं । पिछड़े लोगों का एक बबुलर पूरे देश में खो चला है उसको मन्थालने के दो ही रास्ते हैं । आज हरिजनो को कल करने की बातें सामने आती हैं, हरिजनो पर एंटीसिटिज होती है—इसको आप रोक नहीं सकते हैं । कल तक हमारे बाप दादा को कोई लम्बाई मार देता था तो हमारे बाप दादा उसको सह लेते थे लेकिन आज हम इस पीलीसन में हैं कि अगर कोई भी हमको आंच बिखलावेगा तो हम भी उसकी आंच बाहर निकाल देंगे । तो ऐसी परिस्थिति में संघर्ष होना ही और इसको कोई रोक नहीं सकता है ।

बहुत तक मनु स्मृति की बात है—मैंने तो उसे देखा नहीं है और न पढा है—लेकिन यह आप निश्चयनी है कि अगर कोई बहुत खटिया पर बैठ जाए, तो उसके चूतर काट लो, अगर किसी के मान में वेद का उच्चारण

हो जाए तो उसके कान में सीसा डाल दो, कोई वेद का उच्चारण कर दे तो उसकी जीभ काट लो। इस तरह की भावना पहले से बनी हुई है। धात्र में भी धपने से नीचे वाले को देखता हू तो मुझे बुझी होगी है, मैं समझता हूँ मैं ऊंची जाति का हूँ। इसी तरह वे विनायक बाबू जब मुझे देखते हैं तो उनको भी खुरी होती है लेकिन जब उनके ऊपर किसी ठाकुर की लात पड़ती है तो उनको भी मुस्ता धाता है। इन तरह की जो भावना हैं उसको दबाने के दो ही तरीके हैं। जमीन के गर्भ में तो गरम पत्थर है वह धीरे धीरे निकल जाये करना प्लानामुखी फूटने धीरे बबबबर धायेंगे।

तो मैं यह कहता हू कि हिन्दुस्तान में उम तरह का प्लानामुखी नहीं फूटेंगा धीरे इसके लिए मैं धपनी सरकार से धीरे जनता पार्टी को जो हकूमन हूँ उससे, धीरे धपने मंत्री श्री पाटिल साहब से धाघर कसबा कि पाटिल साहब धात्र इस बात को कबूल कीजिए कि मन्नाज में जो जनरल रूल है उसके धपवाद में धीरे जमजीवन राम हूँ। जमजीवन राम जी सच नहीं है धीरे पिछड़ी जातियाँ में सब लोग ही गजुकेसनही धीरे सोमबी धागे नहीं है, उनमें बहुत से नाय इस मामले में बहुत बैकबद्ध हैं।

इन्होंने डा० राजेन्द्र प्रसाद को बान कहा। डा० राजेन्द्र प्रसाद जब राष्ट्रपति के तब उनको धपने जपगवी के पाव फूने पडे स्पोकि वरु बाहायण है। जमजीवन राम को धाप बान करते हैं। बागणमी म उनको माय क्या हुआ ? धीरे जमजीवन राम जा ने जिस मृति का धनावरण किया उनको धाया गया। जो कौने इस बात को हम नजरान्दाज कर सकत हैं। मन्नाज में जो ऐसी बानें हाती है, उनको तब नजरान्दाज न करने धीरे इम्निग मैं धापसे कहता हू धीरे पहने भी मैंने कहा था कि 'एक अ्यकिन एक राजगार'। एक परिवार में एक राजगार धाप कर दे लेकिन, धात्र इस क्या देखते है कि एक परिवार है, उसमें एक माई कल कागखाने का मायिक है, दुमरा माई बाघ हजाय बाधा जमीन का मायिक है, तीसरा माई धाई० ए० ए० बनने के बाद सेकेटरी होकर राज्य बनाएगा धीरे चौथा माई राजनीति में मंत्री बनकर राज्य बलाएगा यानी एक परिवार का चारो तरफ बर्चस्व है। उसको हम अरम नहीं करते हैं। धपनी इन हाऊम में एक बिल धाया था, यमुना प्रसाद जी का एक बिल धाया था कि राइट टू जीब होना चाहिए, जिसको सरकार ने नहीं माना। सरकार जब राइट टू जीब नहीं मान सकती है, सरकार जब एम्प्लायमेंट एलाऊन नहीं दे सकती है, तो हमने धो एक बिल उम की सीमा के बारे में बहा पर मूक किया है कि 25 साल की बजाय 50 साल नीकरी के लिए उम की सीमा हू धीरे उम उम में जब नीकरी मिलेगी, तो धो, तीन साल नीकरी में रहूँगे। जब धाप कुछ नहीं कर सकने, तो मायिन पीकित लोगों के मन में धाकोष का होना स्वाभाविक है धीरे मैं समझता हूँ कि नीकुरा परिस्थितियों में धीरे विनायक प्रसाद जी का जो विवेक है, वह सही है। बहुत बहू नारा धाया जाता है "संघोप ने बांधी नाठ" -धब धनता पार्टी बन गई है, तो यह धाघर धानता धाहित "धनता पार्टी ने बांधी नाठ", "पिछडा पाये ती मैं

साठ"। जो तमान पिछडा बर्न है, दलित धीरे पीबि लोग हैं।

सभापति महोदय धब धाप ममान कीजिए।

श्री राम बिलास पासवान मैं एक मिनट में ममान कर रहा हू। यह बात नहीं है कि जो हमारा रिजर्वेशन है इसने हमारी धाधिक समस्या का निधान हो जाएगा। यह बात मंत्री है कि हमसे हमारी समस्या का निधान होने वाला नहीं है। यदि सरकारी धकमर ईमानवारीपूर्वक रहें, तो मन्ने के समय उनके पाप एक पैमा भी नहीं रहता है। यह भी धाप देखिये कि बनि एक मनेब बर का लकका है या हरिजन का लकका है धीरे बह करोडपति है, तो उनको भी मलामी करनी पडती है जातियन अ्यवस्था के धाघार पर लेकिन उसी हरिजन का लकका धगर बी० एम० पी० बा एम० पी० बन जाता है तो कोई भी जाति के लोग हाँ, कुली के डर में उनका उनकी मलामी करनी पडती है। इसमें ममाजिक न्याय को बान है धीरे इसमें धीरे कुछ नहीं है।

मभापति महोदय, मैं धापके माध्यम से धपने माननीय मंो जी में धापहू कसबा कि वे इस बिल को सहर स्वीकार कर में जिसमें कम से कम धागे धाने धाने धलित्वाय, धागे धाना वाला मयय यह बनना मके कि जनता पार्टी को जब हकूमन धो नी उसन पिछडे बर्णों के लिए कुछ काम किया।

इन शब्दा के माध में धपता माधन ममान कसता हू।

श्री धोम प्रकाश त्वाणी (बहराच) सभापति महोदय, बान्धव में यह जो धात्र विधेयक धाया है, इसकी भावना का तो मैं धाघर करता हू परन्तु यह विधेयक धपनी मोमामा को लाघ गया है। इम्निग मुने थैके के माध इसका विरोध करना पड रहा है।

में ज्वावा विटेल्लम में तो नहीं जाना बाहता लेकिन इसक पहने एक शब्द पर ही मुझे धापति है। इसमें बर्ण शब्द का प्रयोग किया गया है। मैं यह बताना चाहता कि 'बर्ण' धीरे 'जाति' में अन्तर होता है। बर्ण अ्यवस्था के धाघार जन्म नहीं, गुण, कम धीरे ग्वभाव है। दुर्भावबन, बह धाघार समान हो गया है धीरे जन्म में उनका रूप ले लिया है अ्यथा गुण, कम धीरे स्वभाव के धाघार पर कोई भी योग्यता प्राय कन्के बाहायण बन सकता है, क्षत्रिय बन सकता है धीरे वैश्य बन सकता है धीरे कर्म में बह ऐमा ही सकता है। तो यह जो अ्यवस्था है इनमें जन्म का रूप ले निवा है, जो कि एक विकृत रूप है धीरे जिसके धिनाक रेवोजुन होना चाहिए। बाहित तो यह था कि वर्तमान जन्मयत जातियों को तोडने के लिए धात्र एक विधेयक धाना धीरे कोई रेवोजुन होना। अध्येय अय प्रकार नाघयण जी ने इसी नामयिक रेवोजुन की धीरे हमारा ध्यान धाकधिन किया था धीरे मनष जाति का यही धर्ष था कि जन्म पर धाघारित मोनागोली, को तोडा जाए। धाप ने धाघरन्य की बात कही है। 10 नीकरीयों में धाघरन्य, मैं समझता हूँ, सधार के कनि नी वैक में, बाहू पर प्रभातक की धाघार पर माधन बहता है, धाघरन्य की अ्यवस्था नहीं है। नेकिन

[श्री श्रीम प्रकाश त्यागी]

यहाँ हमारे सचिवालय बनाने वाला न इस दल की परिस्थितियाँ का ध्यान कर के धारण कर लाना किया। क्योंकि मतान्धियों से कुछ लोगों का जानबूझकर भी बुरी हालत में डेक दिया गया था। उन्हें कुछ पर चढ़ने नहीं दिया जाता, घरों में भ्रान्त नहीं दिया जाता। मदिरों में घुसने नहीं दिया जाता था। उन्हें एक प्रकार से नगरों से दूर फेंक दिया गया। ऐसी स्थिति में वह दृष्टिकोण से पिछड़े गये। इसीलिए आज्ञाकारी के बाद हमारे हमारे नरताओं ने उन्हें संरक्षण देना आवश्यक समझा। मैं समझता हूँ कि उन्होंने यह बुद्धिमानी का काम किया। अगर वे यह नहीं करते हम प्रकार से उन्हें संरक्षण नहीं देते तो वे इस देश में प्रति भी अन्वयाय करते और इन लोगों के प्रति भी अन्वयाय करते। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे देश का सामाजिक धार्मिक हाँका सभी कुछ लखबटा जाता। उन्होंने यह किया हम के लिए मैं उन्हें अन्वयाय देता हूँ।

17 hrs

संकेत उनका न हम के लिए आधार बनाया कि जो देश में सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए हैं और विशेष रूप से पिछड़े हुए हैं उनको विशेष सुविधायें दी जायें। उन्होंने प्रारम्भ में अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के लोगों को हम में रखा जो कि सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए हैं। लेकिन उस पर मैं यह कहना चाहूँगा कि जो विशेष कानून बनाया गया वह केवल धार्मिक दृष्टिकोण से पिछड़ों के लिए नहीं था बल्कि जो सामाजिक दृष्टिकोण से भी पिछड़े हुए थे उन के लिये था। उस समय के कानून बनाने वाला मैं इसलिए यह भी कानून बनाया कि अगर कोई हरिजन या अनुसूचित जाति का व्यक्ति हम परिवर्तन कर के किसी और धर्म में जिसे कि सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ नहीं माना जाता है चला जाता है तो उसे मिलने वाली सुविधायें समाप्त कर दी जाएँ। इस बात को व्यवस्था हमारे सचिवालय में है।

सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण से जो लोग पिछड़े हुए हैं और जिनको अभी संरक्षण के लाभ प्राप्त नहीं हुए हैं उनका अधिकार है कि वे संरक्षण की सुविधाओं का लाभ प्राप्त करें। लेकिन इस मामले में मैं यह समझता हूँ कि जो लोग सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण से उन्नत हों। यदि मैं और जा अभी अनुसूचित जातियाँ की कति में हैं उनका भार में गवर्नमेंट को अपनी पालिसी से परिवर्तन करना चाहिए और उनको संरक्षण से प्राप्त होने वाली सुविधाएँ हट कर देनी चाहिए। प्रायः संरक्षण का लाभ और सुविधाएँ उनको ही मिलनी चाहिए जो कि अभी सामाजिक, धार्मिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए हैं। दुर्भाग्यवश हो यह रहा है कि जो सामाजिक-धार्मिक दृष्टिकोण दोनों से उन्नत बन गये हैं और जिन्होंने इन सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर लिया है वे ही इन सुविधाओं का अधिकतम लाभ उठा रहे हैं। वास्तव में इन सुविधाओं का लाभ और संरक्षण का लाभ अब न लोगों को मिलना चाहिए किन्तु तक यह लाभ अब तक नहीं पहुँच पाया है। इसलिए गवर्नमेंट

को अपनी पालिसी में परिवर्तन करना चाहिए ताकि वास्तव में जो सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए हैं, वे उन्नत चढ़ते ही जाएँ और उन्नत समाज का भाग बन जाएँ। जब तक वे यह नहीं बन पाते हैं तब तक उनका लिए संरक्षण चालू रखना चाहिए।

हम सचिवालय विधेयक में कहा गया है कि पिछड़े वर्ग के लोगों का भी संरक्षण दें। हम बारी में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि पिछड़ा वर्ग धार्मिक कौन है? पिछड़े वर्ग का आधार क्या है? दुर्भाग्यवश हम दण्ड में पहलो सरकार द्वारा और इस सरकार द्वारा भी एक बहुत भारी धूल भी जाती रही है जिसका कि प्रभार सुधार नहीं गया तो इस देश में सकोण जाम्हदार्थिकता प्राविवाद और वर्गवाद का समाप्त नहीं होगा अब प्रश्न उठता है कि पिछड़ा वर्ग कौन है? अल्पसंख्यक कौन है? बहुसंख्यक कौन है? क्या जन्म के आधार पर जो इस वर्ग में आता है क्या उन सभी को देश के हित में दृष्टिकोण से संरक्षण मिलना चाहिए? क्या अपने अपने धर्म और सम्पत्ति का पालन करने के लिए संरक्षण मिलना चाहिए? परन्तु सरकार का संरक्षण धर्म या जन्म के आधार पर नहीं देना चाहिए। धार्मिक दृष्टिकोण से भी पिछड़े हुए हैं उन लोगों का सहायता मिलना चाहिए। ऐसे लोग जो औद्योगिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए हैं उनको भी विशेष संरक्षण मिलना चाहिए। मेरी दृष्टि में सरकार को उनको संरक्षण इस रूप में प्रदान करना चाहिए कि उनका बच्चा की स्कूलों में फीस माफ हो और चाहे जहाँ तक पढ़ना चाहे, पढ़ सकें बिना फीस के पूरा उनका स्कूलरजिप मिले उनका बाह्य जान के लिए स्कूलरजिप मिले उनके लिए एक की बार्ड निर्मित हो। कम्प्यूटर मज मजा देना चाहे उनको लिए विशेष क्लासिस लगाई जाएँ ताकि वे योग्यता प्राप्त कर सकें और कम्प्यूटर मज मजा दें।

वर्तमान सूचो जो पिछड़े वर्गों की है उगवा थाप देख। मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ क्योंकि ऐसा करने से किसी की भावना को ठेस पहुँच सकती है। मैं अपने गाँव में संख्या हूँ। वहाँ पर कुछ लोगों ने बाकायदा प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है। उनके पास चार पांच हजार एकड़ जमीन है बड़े बड़े महल हैं। कल परतो मैं हरियाणा गया हुआ था। मुम्हारा जो पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल है, मैं देख कर हैरान हो गया कि उसका एक बहुत बड़ा महल बना हुआ था। बँकि किसी के पिछड़े वर्ग में जन्म लिया है इस लिए वह धार्मिक सुविधा प्राप्त करने का अधिकार बन जाता है इससे बार में सरकार को फिर से सोचना होगा विशेष सुविधा कहाँ प्राप्त है, कहाँ तदे इसको प्राप्तो देवना होगा। धार्मिक दृष्टिकोण से जो पिछड़े लोग हैं उनको प्रायः विशेष सुविधायें दे। अब प्रायः नारसैण बार्ड, परसिड बार्ड से प्रायः उनको दें। कम्प्यूटर के लिए बिजनेस के लिए बीको के सहायता का उनको दिलाएँ। जो धार्मिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए हैं उनको पहले सहायता मिलनी चाहिए, वह

परमिट मिलने चाहियें। दिल्ली में ही प्राप देखें। बुरी माफिट में प्रापको पिछड़े बर्ग के प्रावसी की कोई दुकान नहीं मिलेगी, किसी भी हरिजन की दुकान नहीं मिलेगी। मैं चाहता हूँ कि बाहर के शहर दुकानें बनाई जायें तो उनको दुकानें बीच में दी जाएँ उन दुकानों के धीरे परमिट साइसेंस ट्रेनिंग प्रादि दे कर उनको प्राप बिजनेस धीरे रिक्रियों में प्रवेश दें, उनका प्राप उनमें प्रवेश कराएँ।

मैं ईस्ट अफ्रीका में गया था। वहाँ की सरकार ने पिछड़े लोगों को उपर उठाने की चेष्टा की है। केनिया की सरकार ने एक कानून बनाया कि जो अंगली लोग हैं अफ्रीकी लोग हैं उनको जब तक किसी भी कंसन में पार्टनर नहीं बना लिया जाता है, एक्टिव पार्टनर नहीं बना लिया जाता है धीरे बिना उसकी पूंजी के उसको पार्टनर नहीं बना लिया जाता है तब तक किसी भी कंसन को धीरे नारसेंस नहीं मिलेगा, उसको स्वीकृत नहीं मिलेगी। तीस साल हो गए हैं, अगर हमारे देश में ऐसा काम किया गया होता धीरे इस प्रकार का कानून बना दिया गया होता तो पिछड़े बर्ग के लोग हमारे बराबर आ कर खड़े हो सकते थे, सम्मानित जीवन व्यतीत कर सकते थे। लेकिन कानून बनाने वाले धीरे शासन करने वाले ऐसे लोग थे जो इस प्रकार की बात नहीं चाहते थे। प्राप सीलिंग को ही ले। देश में भूमि पर सीलिंग का कानून बनाया गया। यह कहा गया कि हमने अफ्रीकीनों को भूमि मिलेगी। लेकिन कोई भी भूमि इस कानून से प्रापको नहीं मिली। प्राप ने कानून तो बना दिया लेकिन कुला, बिस्वी, बेल तक के नामों पर भूमि करा कर कर इस सीलिंग के कानून से लोग बच निकले धीरे एक भी एकड़ भूमि प्रापको इस सीलिंग के कानून से नहीं मिल सकी। जो भूमिहीन थे वे ज्यों के त्यों भूमिहीन बने हुए हैं। कानूनों का इम्प्लैमेंटेशन जिन के हाथ में था उनके ही दिल में देईयानी थी, उनके ही दिल में इन लोगों के प्रति सहानुभूति नहीं थी धीरे यह सब उनका नतीजा है। विशेष रूप से धारक्षण के लिए मैं कह रहा हूँ कि मैं उसका पूर्ण समर्थन करता हूँ अनुसूचित जातियों धीरे जन जातियों के लिए धीरे धीरो के लिए भी जिन को इसकी आवश्यकता है। लेकिन मेरी दृष्टि में जन्म धीरे धर्म के आधार पर धारक्षण नौकरियों में नहीं होना चाहिये। केवल आर्थिक दशा सुधारने ही नहीं अपितु पूरे देश का शासन उन लोगों के हाथ में होना जो नौकरियों में प्रापेंगे। वे इंजीनियर डाक्टर बनेंगे धीरे देश के कर्षधार बनेंगे। नौकरियों में समझता हूँ योव्यता के आधार पर ही जानी चाहिये धीरे जन्म धीरे धर्म में नाम पर किसी को नौकरी में धारक्षण देना सिद्धान्तः मैं गलत समझता हूँ। जितनी बात स्वीकार की हुई है गवर्नमेंट ने उसको मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि उनके शर्ताव्धियों तक दबा करके रखा गया है धीरे इस वाले उनके संरक्षण को हम टच न करें। लेकिन प्रापे जो नरक्की है धीरे दूसरे बर्ग जो आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए हैं उनका भी ध्यान किया जाए। उद्यत बर्ग के उपर क्याय लवाई जाए धीरे पिछड़े बर्ग को उपर उठाया जाए धीरे उपर टच इन में उठाया जाए कि देश

के प्रशासनिक ढांचे में कोई फर्क न पड़ने जाए। अगर बाइ ही जिन को हमने संरक्षण के लिए बनाया है वह खेत को खाने लगेगी तो बात गड़बड़ा जाएगी। इसलिए मुझे माफ करिये, मैं इस विधेयक का समर्थन नहीं कर सकता हूँ। मैं इसका सिद्धान्तः विरोध करता हूँ। यह विधेयक अच्छी भावना होते हुए भी देश के लिये हितकर नहीं है।

श्री कृष्णदास सिंह यादव (प्रतापगढ़) : समाजवाद कैसे प्रायेगा? प्राप विरोध कर रहे हैं।

श्री शोब प्रकाश स्वामी : समाजवाद, आर्थिक दृष्टिकोण से मजदूर लड़ते नव प्रायेगा। धर्म धीरे जन्म के नाम पर सबकर न कभी समाजवाद प्राया है धीरे न प्रा यकेगा।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोठरमा) : सभापति महोदय, श्री विनायक प्रसाद यादव के बिल के सदर्थ में मैं यह कहूँगा कि उनकी भावना बस्तुतः सही है क्योंकि प्राजादी को 32 साल हो चुके हैं लेकिन इतने दिनों के बाद भी इस तरह की भावना जोर पकड़ रही है कि नौकरियों में धारक्षण होना चाहिये।

कल ही हमने अलीगढ़ मुस्लिम विश्व-विद्यालय के विषय पर जब विचार चल रहा था तो यही मुना कि अल्प संख्यकों का चरित उसका होना चाहिये, माइनोरिटी करेक्टर होना चाहिये। यह सब बातें ही रही हैं धीरे इतने वर्षों से हरिजन से प्रादिवामी अलग अलग प्राव्योचन कर रहे हैं।

संविधान के अनुच्छेद 14 से 16 के अन्तर यह बताया गया था कि समाज के कमजोर वर्गों की निरन्तर उन्नति की जायगी, उन्हें प्रोत्साहन दिया जायगा, उपर उठाया जायगा। उनका सामाजिक धीरे शैक्षणिक दृष्टिकोण से इतना विकास किया जायगा कि वह समानता के शैल पर प्रा सकें। संविधान की प्रस्तावना में भी समानता, स्वतंत्रता धीरे भाई बारे की भावना प्रादि सारी बातें हैं लेकिन बराबर यह प्राजाज दी जाती रही है कि समाजवादी व्यवस्था लायेंगे। कभी अन्वोधय धीरे कभी सर्वोदय धीरे नाना प्रकार की बातें होती रही हैं। इस के बावजूब भी स्थिति यह है कि कमजोर वर्ग टोड़ तो रहा है, इममें दो मत नहीं हैं, उनकी स्थिति बदली ता है लेकिन अपेक्षाकृत यह बहुत कम हुआ है। इमलिये सारी तरफ एक तरफ से वर्ग सर्वथ की स्थिति सारे देश में पैदा हो गई है। अगर संविधान में दी गई भावनाओं धीरे प्रावधानों का अनुसरण ठीक से किया गया होता, केवल कितानों में ही प्राजाकारी पड़ी नहीं रहती तो प्राज यह स्थिति पैदा नहीं होती। इमलिय जितनी प्रावनाया प्रावधान थे, उनका अमल प्राचा कमेणा के हिसाब से हमारे प्रतिनिधियों या सरकार बनाये बालों को काम करना चाहिये था लेकिन उनकी कयनी धीरे करनी में कोई सामंजस्य

[श्री पीतलाल प्रसाद वर्मा]

नहीं था। उसी का परिणाम यह हुआ है कि आज 32 वर्ष के बाद भी हम तरह की बातें ही रही हैं जब कि सविधान में 20 वर्ष के भारस्मय की बात थी। लेकिन इस अवधि को 32 वर्षों तक चलाया गया है और भाषों भी बढ़ाया जा रहा है और फिर बैकवर्ड का कमीशन बनाया जा रहा है। आज इसकी ज़रूरत क्यों है, समाजिक और औद्योगिक दृष्टिकोण में समाज का उत्तरोत्तर विकास हो जाना चाहिये था। लेकिन यह साफ जाहिर करता है कि हमारे पीछे की जितनी सरकारें बनी हैं सब की नियत साफ नहीं थी। भाषण में कहते रहे कि सामाजिक दृष्टिकोण से समाज के विकास में जितने नेत्र हूए हैं उनके भाषण सुन्दर और प्रशंसनीय हैं लेकिन जब उनकी बातों को कार्यान्वित करने की बात आती है तो वह बिल्कुल कुछ नहीं हो पाता है। यही कारण है कि समाज में बहुत गहरी खाई बनाई हुई है। अगर यह खोजोचन भी हो जाना है तब भी उस खाई को मिटाया नहीं जा सकता है। जब तक व्यक्ति में राष्ट्रियता की भावना नहीं आती है जब तक देश और समाज की प्रति महानुभूति दिल में नहीं होती है तब तक कोई भी मशाघन का कानून जमीन पर नहीं उतर सकता है और इस लिए हरिजन आदिवासियों बैकवर्ड क्लासिफ़ाइड वर्गों का विकास सम्भव नहीं है। लेकिन माननीय सदस्य की भावना वस्तुतः जमीन पर है।

बिहार में भारस्मय का नाम पर सरकार गिरी और बनी। 500 पी० में भी वही स्थिति हुई और यह प्रवृत्ति वनक प्रयास हर एक प्रान्त में बढ़ रही है। हमसे स्पष्ट होता है कि समाज का मशीन विकास होना चाहिए हमारे समाज लोग धनलोभ की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन धनलोभ क्या है? केवल भाषणों में धनलोभ नहीं हो सकता है। प्रश्न यह है कि नीचे के लोगों को ऊपर उठाने के लिए क्या काम किया गया है, उनका कितना विकास किया गया है और उनका स्तर कितना ऊपर उठा है। अगर भावनाओं को कार्य रूप में परिणत नहीं किया जाना है, अगर हमारे विचार केवल किताबों और सिद्धान्तों तक ही सीमित रह जाते हैं तो समाज का दिन कभी भी नहीं हो सकता। 32 वर्ष हो गये हैं पचास वर्ष के बाद भी समाज जहाँ का तहाँ रह जायगा। जो लोग बढ़ रहे हैं वे वातावरण के प्रभाव में बढ़ रहे हैं। बहुत से उच्च विचार और भावनाएँ व्यस्त की जाती हैं, लेकिन उन्हें जमीन पर नहीं उतारा जाता है।

यह सही है कि जनता सरकार के आने बाद सम्पूर्ण कानून या सम्पूर्ण कानून का एक वातावरण बहुत खोरी से बना है, और समाज के पद वसित वर्ग से ले कर उन्नत वर्ग तक में एक भाव अनुभूति हो उठा है कि वे किस तरह आगे बढ़ें बीसवीं सदी की वैज्ञानिक तकनीक में वे पीछे न रह जायें। आज हमके पीछे नये आविष्कार, नये विचार और नई जगृति का काम कर रही हैं। 1977 से

आज तक जनता की सरकार है। लोग अपने विचार व्यक्त करते रहे हैं चाहे वे सरकार के पक्ष में हो या विरोध में।

जब बिहार में हरिजनों पर जुल्म हुआ तो श्रीमती इन्दिरा गांधी हाथी पर सवार हो कर— और हाथी की तरह ऊँची भावना लेकर—वहाँ गईं लेकिन जब बिहार सरकार ने यह निर्णय लिया कि हरिजनों को भालम रखा के लिये हथियार दिये जायें, तो उन्होंने उसके विरोध में विचार व्यक्त किये। हाथी के दाँत खाने के और होते हैं और विधान के और हात हैं। उस तरह की भावना से देश का कल्याण नहीं हो सकता है। अगर समाज का कल्याण करना है, तो उसका औद्योगिक और सामाजिक दृष्टि से विकास होना चाहिए। लेकिन प्राथमिक दृष्टिकोण भी महत्वपूर्ण है।

आज राष्ट्रीय कनिष्ठ और अन्य जातियाँ न ही ऐसे बहुत से लोग हैं जो अधिक दृष्टि से हरिजन और बैकवर्ड क्लासिफ़ाइड के समतुल्य हैं। उनकी भी एक लिस्ट बनाई जानी चाहिए। अगर किसी परिवार का एक प्रायमी किसी क्लास बन क्लास ट, ग, गजटिड या नान गजटिड पास्ट प्राई० ए० ए० प्राई० ए० ए० ए० या प्राई० पी० ए० ए० म नियुक्त हो जाता है, तो उन परिवार का बैकवर्ड क्लासिफ़ाइड की लिस्ट से छिनीट कर देना चाहिए और उसे फार्वर्ड की सूची में जोड़ देना चाहिए चाहे वह परिवार किसी भी वर्ग का हो। अगर किसी हरिजन परिवार का कोई व्यक्ति गिबर्सेनन या लार्गानन हो जाना है, तो उसका भी बैकवर्ड क्लासिफ़ाइड की लिस्ट से निकाल देना चाहिए और फार्वर्ड क्लासिफ़ाइड की लिस्ट में जोड़ देना चाहिए। और फिर दूसरे लोगों का जो उनी बैकवर्ड हरिजन और आदिवासी में से बच जाय उन की दूसरी लिस्ट में रख कर निश्चित रूप से उन को स्याम द। जो एक भाग बढ़ जाय वह उन लाइन में भाग बढ़ सकते हैं।

इसी तरह जो उच्च वर्ग के लोग हैं उन में भी जा गरीब तबके में हैं जिनकी प्राथमिक स्थिति बहुत दयनीय है उनकी भी लिस्ट बननी चाहिए, इसके द्वारा ही इनका भी उत्थान हो सकता है। यह सरकार का विचार केवल विचार रह जायें तो यह ठीक नहीं है और यही कारण है कि इतने वर्षों के बाद जितनी नौकरियाँ हैं उनमें कुछ ही वर्गों के लोगों के लिए प्राधान्य आती है कि उच्च वर्ग के लोगों की संख्या देश में 15 प्रतिशत है और नौकरियों में इन वर्ग के लोग 40 प्रतिशत हैं तथा पिछड़े, हरिजन और आदिवासियों की संख्या 85 प्रतिशत है लेकिन नौकरियों में वे लोग 15 प्रतिशत हैं। ता उचित नहीं है। हम समझते हैं कि हर वर्ग के घर घर की देखा के नीचे जो लोग हैं चाहे वह राष्ट्रीय कनिष्ठ या वैश्व छोड़े भी हो, उनको न्यायोचित ढंग से लिस्ट बनाकर स्थान मिलना चाहिए और जिस परिवार में जिस किसी को भी नौकरी मिल जाय उन को विनीट करने दूसरे लोग जो बच जाय उन की लिस्ट बनाकर उनको स्थान दिया जाय ताकि समाज के जो पिछड़े

वर्ग के लोग हैं उनका उचित स्थान मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विषय की जायनामों का समर्पण करता हूँ।

MR. CHAIRMAN: I will call Mr. Mahilal. That is the last name. There are two other speakers also with me.

As per time schedule, 2 hours will be over by 5.33 p.m. Moreover, there are certain other items also—Bills to be introduced. I do not know what to do. Hon Members do not give their names earlier so that a proper estimate can be framed. What happens is that at the start of the discussions of the Bill, there were only two names. So the first speaker was given a longer time. Now it will be difficult and it will be against the interests of the hon. Members who are waiting here to move their Bills. I think the House should co-operate.

PROF. P. G. MAVALANKAR (Gandhinagar) Members get ideas only after listening to some of the speeches!

श्री विनायक प्रसाद शास्त्र महोदय यह बहुत इम्पोर्टेंट बिजनेस है और दूसरे माननीय सदस्य का जो है वह भी महत्वपूर्ण है तो उसको भी मुझ करवा दिया जाय और इसको कन्टीन्यू रखें।

सभापति महोदय ऐसा विधान के अनुसार नहीं हो सकता।

श्री विनायक प्रसाद शास्त्र दो इस को चलने दिया जाय।

MR. CHAIRMAN: It cannot be done only for some members who come late and want to speak. I think it is not a good precedent and it will not be fair also. If the members are serious, they should give their names early so that a proper planning can be done as to how much time can be allotted to each member.

Now, Mr. Mahilal—you will take only 5 minutes.

SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN (Coimbatore): I have a Bill.

My Bill is a very important one affecting lakhs and lakhs of Bidi workers who are the most exploited in the country. And it seems that all these people are the least concerned about these exploited workers.

MR CHAIRMAN: I am afraid now it cannot be finished today.

SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN. Anyway you are not interested in the interests of the Bidi workers.

MR. CHAIRMAN: Everybody is interested, but how can we help it?

I am told the hon Speaker has been kind enough to permit you.

Mr. Mahilal

श्री श्री लाल (बिजनौर) सभापति महोदय, धारण की मांग सामाजिक और धार्मिक विषयों के उद्धार से पैदा हुई है। सामाजिक और धार्मिक विषयों से केवल अनुचित जातियाँ, अनुचित जातियों और पिछड़ी जातियाँ ही पीड़ित नहीं हैं, ऐसा नहीं है। सभी मुझे एक दो दिन पहले उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से एक सूचना मिली है। वैश्य परिवार में पैदा होने वाले एक सुपरिटेन्डिंग इंजीनियर का नाम शेर सिंह था। बलिया जिले में मान्यता है कि सिंह पर केवल क्षत्रियों के नाम हो सकते हैं। वैश्य परिवार में पैदा होने वाले व्यक्ति का नाम सिंह पर नहीं हो सकता। ता शेर सिंह माहब सुपरिटेन्डिंग इंजीनियर को केवल इन लिए पीटा गया है उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में कि वैश्य परिवार में पैदा होने हुए उन्होंने अपना नाम शेरसिंह क्यों रखा। इस उदाहरण से धार्मिक अनुमान हो जायगा कि हमारा मूढ़ समाज सामाजिक विषयों का लिकार है, कोई कम और कोई ज्यादा। वैश्य परिवार के लोग भी सिंह का नाम होने के कारण पीट सकते हैं, जाकि सम्मान है, सुपरिटेन्डिंग इंजीनियर है। यदि उनका नाम शेर सिंह था इसलिए उनका पीटा गया और वह भी एक कनकट के बगले पर। (अव्यक्त) इस बात का मुझे पता नहीं है कि कनकट हरिजन था या नहीं। तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि धारण की मांग सामाजिक और धार्मिक विषयों के उद्धार से पैदा हुई है। अब एक सामाजिक जागृति आई है इसलिए धार्मिक इस मांग को रोक नहीं सकते हैं जब तक कि सामाजिक धार्मिक विषयों का समाधान नहीं हो जायगी।

MR. CHAIRMAN: Mr. Mahi Lal, just a minute. May I know the House how much time is required for this

[Mr. Chairman]

Bill? The hon. Minister has to reply and then the mover has also to reply to this. How much time more does the House want to give to this Bill—not to-day—for the next time?

SEVERAL HON. MEMBERS. Another half-an-hour.

SHRI K. LAKKAPPA: Please do not take away my time.

SHRI R. L. KUREEL (Mohanlagan): One hour may be given next time.

PROF. P. G. MAVALANKAR: You said that initially there were only two members who had given their names.

SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN: You have indicated to us that you have got two more names. And then the Minister has to reply. The mover has also reply. Two hours only were allotted for this Bill. In this way you go on adding the names in the list as and when the Members give their names. I say that there should be not more than half-an-hour's time given to this bill.

MR CHAIRMAN: Is it the pleasure of the House that the time should be extended by half-an-hour?

SEVERAL HON MEMBERS: Yes, yes.

PROF. P. G. MAVALANKAR: No more names should be added to the list.

MR. CHAIRMAN: Mr Mahi Lal, you may finish your speech next time. Next time the hon. Minister and the mover only will reply. Now, the Speaker has permitted Shri Saugata Roy to introduce his Bill Mr Saugata Roy.

17.28 hrs.

COMPANIES (AMENDMENT) BILL*

(Substitution of Sections 275, 276, etc.)

SHRI SAUGATA ROY (Barrack-

pore): Sir, I move for leave to introduce a Bill further to amend the Companies Act, 1956.

MR CHAIRMAN: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Companies Act, 1956"

The motion was adopted.

SHRI SAUGATA ROY: Sir, I introduce the Bill.

MR CHAIRMAN: Mr Ram Jethmalani. Mr Speaker has permitted him.

EMERGENCY COURTS BILL

SHRI RAM JETHMALANI (Bombay-North West): I move for leave to withdraw the Bill to provide for establishment of Emergency Courts for the trial of a certain class of offences.

SHRI K. LAKKAPPA (Tumkur): Sir, it is dangerous to do so. You blackmailed this Parliament. Now he is withdrawing the Bill on establishment of Emergency Courts. I charge you have conspired and showed vindictiveness for the establishment of special court and have blackmailed the Parliament by now withdrawing your Bill.

MR CHAIRMAN: The question is:

"That leave be granted to Shri Ram Jethmalani to withdraw the Bill to provide for establishment of Emergency Courts for the trial of a certain class of offences".

The motion was adopted.

SHRI RAM JETHMALANI: I withdraw the Bill.